

स्टैंड अप इंडिया

- स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इस योजना का संचालन वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
- स्टैंड-अप इंडिया योजना ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये से कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता और बैंक शाखा के प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला उधारकर्ता के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवाओं या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है। गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% हिस्सेदारी और नियंत्रण हिस्सेदारी एससी / एसटी या किसी के पास होनी चाहिए महिला उद्यमी।

लाभ

- महिला सशक्तिकरण
- रोजगार पैदा करेगा

पात्रता

- 18 वर्ष से अधिक आयु के एससी / एसटी और / या महिला उद्यमी।
- इस योजना के तहत ऋण केवल हरित क्षेत्र परियोजना के लिए उपलब्ध हैं। ग्रीन फील्ड इस संदर्भ में, निर्माण या सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में लाभार्थी का पहला उद्यम है।
- गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी एससी / एसटी और / या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।

- उधारकर्ता किसी भी बैंक / वित्तीय संस्थान के लिए डिफॉल्ट रूप से नहीं होना चाहिए।

दस्तावेज और आवश्यक स्थिति

- पहचान का प्रमाण: मतदाता पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / पैन कार्ड / हस्ताक्षरकर्ता के वर्तमान बैंकों से हस्ताक्षर, निदेशक का साथी (यदि कोई कंपनी है)

निवास का प्रमाण: हाल के टेलीफोन बिल, बिजली बिल, संपत्ति कर रसीद / पासपोर्ट / मतदाता पहचान पत्र, प्रोपराइटर, निदेशक का पार्टनर (यदि कोई कंपनी है)

- व्यापार पते का प्रमाण
- आवेदक किसी भी बैंक / एफ.आई. में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए
- कंपनी के सहयोग का ज्ञापन और लेख / पार्टनरशिप डीड ऑफ पार्टनर आदि।
- नवीनतम आयकर रिटर्न के साथ प्रमोटर्स और गारंटियों के आस्तियों और देनदारियों का विवरण।
- रेंट एग्रीमेंट (यदि किराए पर व्यावसायिक परिसर है) और लागू होने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी।
- यदि लागू हो तो एसएसआई / एमएसएमई पंजीकरण।
- वर्किंग कैपिटल लिमिट के मामले में और टर्म लोन के मामले में लोन की अवधि के लिए अगले दो साल के लिए प्रॉजेक्टेड बैलेंस शीट
- प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में पेश की जा रही सभी संपत्तियों के लीज डीड्स / शीर्षक कर्मा की फोटोकॉपी।
- आवेदक एससी / एसटी श्रेणी से संबंधित है, जहां भी लागू हो, यह स्थापित करने के लिए दस्तावेज।

•से निगमन का प्रमाण पत्र यह स्थापित करने के लिए कि कंपनी में बहुसंख्यक हिस्सेदारी एससी / एसटी / महिला वर्ग से संबंधित व्यक्ति के हाथों में है या नहीं।

किसी भी प्रश्न के लिए वेबसाइट पर जाएँ

["http://vikaspedia.in/social-welfare/scheduled-caste-welfare-1/stand-up-india-scheme"](http://vikaspedia.in/social-welfare/scheduled-caste-welfare-1/stand-up-india-scheme)